

जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक ही नगर निगम रहेगा : झाबर सिंह खर्वा

प्रदेश में एक शहर-एक निकाय लागू होगा; 2025 में एक साथ होंगे चुनाव

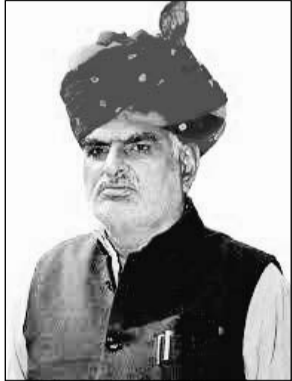
-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। जयपुर, जोधपुर और कोटा में पुनः एक ही नगर निगम बनेगा। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्वा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इन निकायों के टुकड़े कर दो-दो नगर निगम बनाने के फैसले को बदलने की बात साफ कह दी है। खर्वा ने कहा कि राजस्थान में "एक शहर-एक निकाय" लागू होगा, वर्ष 2025 तक इन तीनों शहरों में एक साथ चुनाव करावाए जाएंगे।

बड़े पैमाने पर मर्ज हो सकते हैं वार्ड

सूत्रों की मानें तो "एक शहर-एक निकाय" के लिए बड़े पैमाने पर बनाए गए वार्ड मर्ज हो सकते हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा में फिर से एक-एक नगर निगम के हिसाब से वार्ड बनाने होंगे। इससे वार्डों का पुनर्गठन होगा। इस प्रक्रिया में समय बचाया जायेगा। एक शहर, एक निकाय लागू करने से तीनों शहरों में नगर निगम की व्यवस्थाएँ बदलेंगी। इसका असर निकाय चुनावों पर भी होगा। दो-दो की जगह फिर से इन शहरों में एक ही मेयर होगा। वार्ड मर्ज किए तो पार्षदों की संख्या भी घटेगी।

कई निकायों में लगे प्रशासक

"एक राज्य-एक चुनाव" करवाने की हालत में राज्य सरकार को कई निकायों में प्रशासक लगाने होंगे। यूपीएच मंत्री ने निकायों में प्रशासक



झाबर सिंह खर्वा

लगाने की तैयारी के संकेत दिए हैं। एक साथ चुनाव करवाने के कारण जिन निकायों के चुनाव इस साल बाकी हैं, उनके चुनाव अगले साल तक के लिए टालने होंगे। शहरी सीमाएँ, वार्ड बदलने में अभी जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक है। "एक शहर, एक निकाय" और वार्डों के पुनर्गठन में सबसे बड़ी बाधा जनगणना है, फ्री 1 जुलाई से प्रशासनिक सीमाएँ प्रती बनाने के आदेश जारी हो चुके हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह रोक हटाने तक सरकार वार्डों से लेकर शहर-जिले तक की सीमा में कोई बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे हालात में वार्डों परिसीमन भी नहीं हो सकता, न वार्डों के बदल सकती हैं। वार्डों के परिसीमन के बिना निकायों के चुनाव आगे बढ़ाने का कोई कानूनी रास्ता भी नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि वार्ड परिसीमन का तर्क देकर सरकार चुनाव आगे बढ़ा सकती है, लेकिन बिना रोक हटाने पर संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने 4 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के नई प्रशासनिक यूनिट बनाने, जिले, शहर, गांव, वार्डों की सीमाएँ बदलने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। केंद्र की तरफ से इस मामले में फिलहाल कोई छूट नहीं मिली है।

सीमांकन विवाद से परेशान हैं लोग

जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर

निगम के दो टुकड़े करने के बाद सीमांकन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुए। सफाई, सीवरेज, गार्डन, आवारा पशु और पट्टे जैसे मुद्दों को लेकर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी आपस में ही उलझे रहते हैं। जब किसी जिम्मेदारी की बात आती है तो अधिकारी और कर्मचारी उसे दूसरे निगम का बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं और भुगतना जनता को पड़ता है।

उदाहरण के तौर पर जयपुर नगर निगम में ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र में अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने पहुंच गई थी, लेकिन जब उन्हें सीमा का पता चला तो बिना कार्रवाई के ही लौटाना पड़ा था। जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा था कि भले ही डेयरी हैरिटेज क्षेत्र में है, लेकिन वहां के आवारा पशु ग्रेटर को गंदा कर रहे हैं। इसी तरह सफाई और सड़क जैसे मुद्दों को लेकर भी दोनों निगमों में टकराव बना हुआ है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का टोक्यो में हुआ ज़ोरदार अभिनंदन



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जापान के टोक्यो पहुंचने पर प्रवासी राजस्थानियों ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैवा और अन्य प्रतिनिधिमंडल का भी तिलक लगाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया।

टोक्यो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दो दिवसीय यात्रा पर सिसोल से जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने पर निजी होटल में भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश संयोजक व ज्वेलर असोसिएशन के उपाध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाला ने यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन के चैयरमैन नवीन सौखियां के संयुक्त नेतृत्व में प्रवासी राजस्थानियों ने ज़ोरदार गर्मजोशी के नारे "स्वागत राजस्थान" मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। राजू मंगोड़ीवाला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत व मुख्यमंत्री

भजनलाल शर्मा का आपणों अग्रणी राजस्थान के तहत दिसंबर में होने वाली राजस्थान राईंग मीट हेतु जापान में रह रहे भारतीय व राजस्थानी प्रवासियों में उत्साह है और बड़ी संख्या में निवेशक जापान में होने वाली रोड शो मीटिंग में जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैवा व अन्य प्रतिनिधि मंडल का भी तिलक लगाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ राजस्थान के संयोजक राजू मंगोड़ीवाला, जापान

राजस्थान प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नवीन सौखियां, गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र, इण्डस्ट्रियल कौशल शर्मा, संगीता शर्मा, श्रीकांत बड़वे, किरण शाह व किशोर तिलवानी सहित दर्जनों व्यवसायियों व प्रवासी बंधुओं की उपस्थिति रही। जापान से जुड़े राजस्थानी प्रवासी व यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन के चैयरमैन नवीन सौखियां ने बताया कि कोरोना काल के समय भी टीम ने वर्चुअल रूप से जुड़कर मानवीयता के इस विषय पर स्थिति में सहयोग किया था।

निजी भूमि पर सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर तहसील स्थित निजी कृषि भूमि पर सीसी रोड निर्माण करने पर मुख्य सचिव और कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकपक्षीय न्याय आदेश शरीर देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी धन का उपयोग कर निजी भूमि पर सड़क निर्माण कैसे किया गया है। याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की सांगानेर तहसील के ग्राम गवार ब्राह्मणान में कृषि भूमि है। पंचायत समिति ने अन्य स्थानीय अधिकारियों से मिलकर उसकी इस जमीन पर अवैध रूप से सीसी रोड का निर्माण कर लिया। ग्राम विकास

अधिकारी की जांच में भी सामने आया कि याचिकाकर्ता की निजी कृषि भूमि पर अवैध तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है और उसके रोड निर्माण के लिए आर्किटेक्ट सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में जिम्मेदारों से इस राशि की रिकवरी की बात भी कही गई। याचिका में कहा गया कि ग्राम पंचायत निजी भूमि पर रोड निर्माण कैसे कर सकती है। इसलिए अवैध रूप से हुए सड़क निर्माण की स्वतंत्र जांच कराई जाए। वहीं याचिकाकर्ता की भूमि पर बनी इस रोड को हटवाया जाए और याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए उसे उचित क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपक्षीय न्याय संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

पूरी संवेदनशीलता से हो उपभोक्ताओं की सुनवाई:डोगरा

जयपुर। डिस्कॉस चैयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने डिस्कॉस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनें और उनका समुचित निराकरण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मीटर बदलने, लोड बढ़ाने, नए बिजली कनेक्शन, बिल में त्रुटि सुधार जैसे आमजन से जुड़े जरूरी कार्यों के लिए उपभोक्ताओं को दफ्तर के बार-बार चक्कर न काने पड़ें। डिस्कॉस चैयरमैन ने मंगलवार को आमेर कुंडा की ढाणी स्थित जयपुर जिला सफिल थिअर जयपुर शहर सफिल के सहायक अभियान कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। डोगरा ने इन कार्यालयों में मीटर, भंडार, राजस्व, रिकवरी एवं उपभोक्ता शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सीट पर मौजूद कार्मिकों से खराब एवं जले हुए मीटर बदलने, लिंबित कनेक्शनों की स्थिति, सैटलमेंट एवं वीसीआर प्रकरणों, बिलिंग, रिकवरी, ट्रांसफॉर्मरों की उपलब्धता एवं उन्हीं बदलने की प्रक्रिया की जानकारी ली।

बारिश से टूटी सड़कों और सफाई पर ध्यान दें निकाय : राजेश यादव

जयपुर। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग खराब हो चुकी सड़कों को दुरुस्त करने में जुट गया है। आमजन से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने नगरीय निकायों में विभिन्न प्रकार के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय उप निदेशक, नगरीय निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी जुड़े।

राजेश यादव ने समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) को निर्देशित किया कि वे अपने संभाग में सबसे दूर और सबसे गंदे वार्ड का निरीक्षण करें। राजेश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण व संवर्द्धन पर भी उतना ही ध्यान दें। यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लिम्बित मुद्दों की समीक्षा की। साथ ही अन्नपूर्णा रसाई के लिम्बित भुगतान और इंदिरा गांधी शहरी गार्टी रोजगार योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी नगरीय निकायों से बजट के अनुसार घोषणाओं के लिए लिम्बित भूमि



स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक ली।

प्रकरण, लिम्बित बजट घोषणाएँ, विधानसभा में लिम्बित प्रश्न, लोकयुक्त, मानवाधिकार प्रकरण एवं आरटीआई के लिम्बित जवाबों को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने लिम्बित प्रकरणों को लेकर सुझावों को लेकर भी चर्चा की और जल्द से जल्द इन्हें निपटाने के निर्देश दिए। आमजन को ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने कहा कि सभी नगरीय निकायों

को इसी प्रकार कार्य करना चाहिए, जिससे लिम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रतिशीघ्र हो सके एवं आमजन के लाभ मिल सके। उन्होंने ऑनलाइन सर्विस के ऊपर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त निदेशक श्याम सिंह शेखावत, उपनिदेशक नवीन यादव, मुख्य अभियन्ता अरुण व्यास, मुख्य अभियन्ता प्रदीप गर्ग, सहायक निदेशक सरकता शोलावती मीणा, श्रीअन्नपूर्णा रसाई जोरदार के स्टेट नोडल ऑफिसर नवीन भारद्वाज मौजूद थे।

देवनानी ने दधीचि जयन्ती समारोह के स्टीकर का विमोचन किया

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधान सभा में दधीचि जयन्ती समारोह के स्टीकर "रक्तदान-नेत्रदान-देहदान-महादान" का विमोचन किया। देवनानी ने समारोह के लिये शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि रक्तदान, नेत्रदान और देहदान मानव जीवन के लिये महादान है। लोगों को दानवीर महर्षि दधीचि के त्याग के अनुरूप मानव सेवार्थ के लिये स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। इस मौके पर राजस्थान प्रांतीय दधीचि (दाहिमा) ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राघव शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक सूटवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र भाभडा, प्रदेश संयोजक शंकर लाल शर्मा, गौरव भाभडा और रघुवीर दधीचि मौजूद थे।

वारे में सभी को विस्तार से जानना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए दुआ-ए-मार्गफिरत की एवं देश में अमन, चैन, खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यध्यय प्रभारी मुकेश पारीक, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एम. सादिक खान, मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जंग बहादुर पठान, प्रदेश मंत्री मुराद अली शेख, जयपुर शहर जिला महामंत्री एम. परवेज खान, जिला मंत्री नदीमुनीम अंसारी, भाजपा मण्डल महामंत्री संयुम अली, मण्डल अध्यक्ष इकबाल हुसैन, मण्डल महामंत्री मोहम्मद हाशिम खान सहित मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

चिकित्सा विभाग व सी.आई.एफ.एफ. में एमओयू

जयपुर। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिल्ड्रेन्स इन्वेस्टमेंट फण्ड फाउंडेशन (सीआईएफएफ) के बीच मंगलवार को शासन सचिवालय में एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एमओयू पर चिकित्सा विभाग की ओर से प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ एवं सीआईएफएफ की ओर से कार्यकारी निदेशक मंजुला सिंह ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव श्रीमती राठौड़ ने कहा कि एमओयू से प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में तकनीकी सहयोग प्राप्त होगा। राज्य के परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी मजबूत किया जा सकेगा। साथ ही, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता होगी। सीआईएफएफ के माध्यम से एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर उपचार विकल्प तैयार किए जाएंगे। राठौड़ ने बताया कि इस पांच-वर्षीय एमओयू के तहत महिलाओं और



बच्चों के जीवन स्तर में सुधार पर फोकस किया जाएगा। एमओयू के तहत सीआईएफएफ की ओर से विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधारत्मक गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा।

सीआईएफएफ के संस्थापक सर क्रिस हॉर्न ने कहा कि एकिकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को स्थितिगत बेहतर होगा। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में राजस्थान

सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के साथ सीआईएफएफ की लंबी साझेदारी रही है। उनका फाउंडेशन बच्चों के लिए एक स्वस्थ, भेदभाव मुक्त और सुशिक्षित तातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. भारती दीक्षित, निदेशक आरसीएच डॉ. सुनील सिंह पानावत, एसपीएम डॉ. लोकेश चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी एवं सीआईएफएफ व जपाईंगो संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कुख्यात सोना तस्कर मुनिय्याद यूई से गिरफ्तार

जयपुर। खाड़ी देशों से भारत में सोने की अवैध तस्करी करने वाले कुख्यात तस्कर मुनिय्याद अली को पुलिस ने यूई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल की मदद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसे यूई भारत ले आई है। मुनिय्याद ने ही खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड तस्करी का अवैध नेटवर्क तैयार किया है। वह चार साल से फरार था। अब मंगलवार को उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद इनपुट मिला कि मुनिय्याद यूई में है। यहां यूई और आवृधावी की टीमों की मदद से उसे पकड़कर भारत लाया गया। इसके बाद उसे एनआईए की टीम को सौंप दिया गया है। अब तक की जांच में सामने आया था कि मुनिय्याद इंटरनेशनल गोल्ड तस्करी के नेटवर्क में शामिल है। मुनिय्याद ने अपने साथियों के साथ मिलकर रियाद, सऊदी अरब से भारत में सोने की अवैध तस्करी का प्लान और नेटवर्क तैयार किया था।

रवि जैन ने किया विरासत संग्रहालय का निरीक्षण



जयपुर। पर्यटन शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को किशनपोल बाजार स्थित विरासत संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने हवामहल स्मारक का अवलोकन किया और जलमहल का भी दौरा कर वहां सौंदर्यकरण, बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए संभावनाओं को समझा और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान पर्यटन सचिव ने विरासत संग्रहालय की रूफ पर रेस्टोरेंट बनाने की सम्भावनाओं पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया। वहीं हैरिटेज वॉक के रास्ते का निरीक्षण कर हवा महल को अंदर से देखा। उन्होंने विशेष तौर पर विभिन्न दरवाजों पर बैतरतीव लगे वायर,

केबल को देखकर उनको व्यथित करने के निर्देश दिए। जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो। रवि जैन ने न्यू गेट के बाहर अजमेरी गेट की तर्ज पर पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य किये जाने संभावनाओं लिए मौका मुआयना किया। शासन सचिव ने इस दौरान स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा, पुरातत्व विभाग की रूफ पर रेस्टोरेंट बनाने की सम्भावनाओं पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया। वहीं हैरिटेज वॉक के रास्ते का निरीक्षण कर हवा महल को अंदर से देखा। उन्होंने विशेष तौर पर विभिन्न दरवाजों पर बैतरतीव लगे वायर,

पार्किंग स्थल पर अव्यवस्था हेरिटेज निगम व ठेकेदार पर हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने पार्किंग स्थल पर अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में हेरिटेज नगर निगम, ठेकेदार व गणपति प्लाजा के जोड़पट्टे पर संयुक्त तौर पर 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश दीपक वर्मा के परिवार पर दिए। आयोग ने कहा कि पार्किंग स्थल पर नगर निगम का बोर्ड और ठेकेदार के नंबर होने चाहिए, लेकिन अधिकार स्थानों पर ना तो बोर्ड होता है, ना ठेकेदार के नंबर और उसके ठेके की अवधि भी नहीं होती। इस के चलते इन जगहों पर आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

परिवार में कहा गया कि वह 10 अप्रैल 2023 को दोपहर बाई बजे अपने दुपहिया वाहन को गणपति प्लाजा के बाहर खड़ा कर गुलाब चाय वाले के पास बैठा था। वह 15 मिनट बाद जब अपने वाहन के पास पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति आया और खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर 15 रुपए पार्किंग शुल्क वसूलें। परिवारी ने घर जाकर देखा तो पता चला कि यह शुल्क 2 घंटे के लिए था। इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि पार्किंग स्थल पर कहीं पर भी बड़े अक्षरों में शुल्क व अवधि के बारे में नहीं लिखा था। वहीं पार्किंग पर्ची पर भी शुल्क और उसके ऑफिसर का पता भी अंकित नहीं था। ऐसे में गणपति प्लाजा के बाहर सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा कर पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। नगर निगम ने जवाब में कहा कि उन्होंने 26 मई 2023 से 25 मई 2024 को अवधि के लिए ई-अविवेशन कर पार्किंग का ठेका दिया है। परिवादी की ओर से पेश पर्ची में कहीं पर भी हेरिटेज निगम नहीं लिखा है, इससे उनका कोई संबंध नहीं है। आयोग ने दोनों ओर की बहस सुनकर कहा कि पर्ची पर ठेकेदार के दस्तखत हैं, लेकिन यह चौकाने वाला है कि परिवादी से 15 मिनट के लिए 15 रुपए वसूलें है।

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्वा ने निलंबन कार्रवाई की बात स्पष्ट की

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। हैरिटेज नगर निगम जयपुर की महापौर मुनेश गुर्जर को राज्य सरकार बुधवार शाम तक निलंबित कर देगी। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्वा ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि, महापौर मुनेश गुर्जर को 24 घंटे में (बुधवार तक) सुबखबरी मिला जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर मेयर मुनेश के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। अब वह किसी भी परिस्थिति में नहीं बच सकती। पहले उनके निलंबन की कार्रवाई होगी, उसके बाद हैरिटेज निगम के पार्षदों में से कार्यवाहक महापौर बनाया जाएगा। चूंकि जयपुर हैरिटेज निगम में महापौर की ओ.बी.सी. महिला सीट होने के कारण भाजपा इसी वर्ग से अपना कार्यवाहक महापौर बनायेगी।

ज्ञात रहे कि मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को ए.सी.बी. ने पट्टे बनाने की एवज में 41 लाख रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि पट्टे जारी करवाने के लिए दो दलालों के जरिए रिश्वत मांगी गई थी। सुशील के साथ दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे को भी गिरफ्तार किया था। उस वक्त एसीबी की ओर से महापौर मुनेश के घर से तलाशी में पट्टे की फाइलें मिली थीं। इसके साथ ही 41 लाख रुपए भी मिले थे। वहीं दलाल नारायण सिंह के घर से भी 8.95 लाख रुपए मिले थे। इस प्रकरण की जांच एसीबी द्वारा की जा रही थी। उस समय मुनेश को मेयर पद

से निलंबित किया गया था, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द कर दिया था। वहीं सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस की भी गिरफ्तार किया था। उस वक्त एसीबी की ओर से महापौर मुनेश के घर से तलाशी में पट्टे की फाइलें मिली थीं। इसके साथ ही 41 लाख रुपए भी मिले थे। वहीं दलाल नारायण सिंह के घर से भी 8.95 लाख रुपए मिले थे। इस प्रकरण की जांच एसीबी द्वारा की जा रही थी। उस समय मुनेश को मेयर पद

से निलंबित किया गया था, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द कर दिया था। वहीं सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस की भी गिरफ्तार किया था। उस वक्त एसीबी की ओर से महापौर मुनेश के घर से तलाशी में पट्टे की फाइलें मिली थीं। इसके साथ ही 41 लाख रुपए भी मिले थे। वहीं दलाल नारायण सिंह के घर से भी 8.95 लाख रुपए मिले थे। इस प्रकरण की जांच एसीबी द्वारा की जा रही थी। उस समय मुनेश को मेयर पद

से निलंबित किया गया था, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द कर दिया था। वहीं सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस की भी गिरफ्तार किया था। उस वक्त एसीबी की ओर से महापौर मुनेश के घर से तलाशी में पट्टे की फाइलें मिली थीं। इसके साथ ही 41 लाख रुपए भी मिले थे। वहीं दलाल नारायण सिंह के घर से भी 8.95 लाख रुपए मिले थे। इस प्रकरण की जांच एसीबी द्वारा की जा रही थी। उस समय मुनेश को मेयर पद